समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 23 September 2026

ऑनलाइन मनी गेम मे नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं, सरकार ने पेश किया सख्त प्रस्ताव

Publisher

Published on 03 Oct 2025

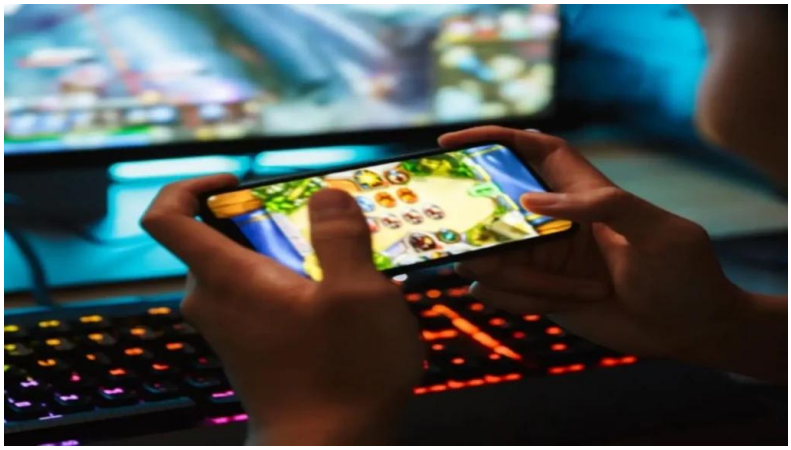

ऑनलाइन मनी गेमिंग क्षेत्र में नियम तोड़ने वालों की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। केंद्र सरकार ने इस दिशा में सख्त कदम उठाने का प्रस्ताव पेश किया है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यदि कोई भी ऑनलाइन मनी गेम के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे अब गैर-जमानती अपराध के तहत गिरफ्तार किया जा सकेगा। इस प्रस्ताव का मकसद गेमिंग प्लेटफॉर्म और उपयोगकर्ताओं के बीच जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है।

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि नियमों के उल्लंघन में सिर्फ खेल में शामिल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि गेमिंग कंपनी का पूरा स्टाफ भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कंपनियों को अपने संचालन और कर्मचारियों की निगरानी सुनिश्चित करनी होगी। किसी भी प्रकार की अनियमित गतिविधि होने पर पूरे संगठन को कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाया जा सकता है।

प्रस्ताव के अनुसार, नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वारंट के बिना तलाशी और गिरफ्तारी की भी अनुमति दी जाएगी। इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग में पारदर्शिता और सुरक्षा बनी रहे। सरकार का मानना है कि यह नीति डिजिटल गेमिंग क्षेत्र में अनुशासन और नैतिकता को बढ़ावा देगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में नियमों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ यह कदम आवश्यक था। पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन मनी गेमिंग की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है, लेकिन साथ ही नियमों की अनदेखी और धोखाधड़ी के मामले भी सामने आए हैं। इस नए प्रस्ताव से गेमिंग कंपनियों पर भी दबाव पड़ेगा कि वे अपने प्लेटफॉर्म को सुरक्षित और पारदर्शी बनाएं।

केंद्रीय अधिकारियों ने बताया कि इस नई नीति के लागू होने के बाद सरकार को यह अधिकार होगा कि किसी भी समय किसी प्लेटफॉर्म या उसके कर्मचारियों की गतिविधियों की जांच की जा सके। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना

और डिजिटल गेमिंग में धोखाधड़ी के मामलों को रोकना है।

इस नीति का सीधा असर गेमिंग उद्योग पर भी पड़ेगा। कंपनियों को अपने स्टाफ को नियमों के पालन के लिए प्रशिक्षित करना होगा और प्लेटफॉर्म पर होने वाली सभी वित्तीय लेन-देन और गेमिंग गतिविधियों की निगरानी करनी होगी। नियमों की अनदेखी किसी भी कर्मचारी या प्रबंधन के लिए गंभीर कानूनी परिणाम ला सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के कदम से ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में भरोसा बढ़ेगा और वैध कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाने का अवसर मिलेगा। इससे उपयोगकर्ताओं के लिए भी यह भरोसेमंद वातावरण बनेगा कि उनके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होगी।

सरकार का यह प्रस्ताव डिजिटल गेमिंग इंडस्ट्री के लिए नए मानक तय करेगा। इसके तहत गेमिंग कंपनियों को न सिर्फ अपने उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना होगा, बल्कि वे अपने स्टाफ की निगरानी और प्रशिक्षण पर भी ध्यान देंगे। इस कदम को लेकर उद्योग में भी मिश्रित प्रतिक्रिया है। कुछ विशेषज्ञ इसे आवश्यक और समय की मांग मान रहे हैं, जबकि कुछ कंपनियां इसे अतिरिक्त दबाव के रूप में देख रही हैं।

इस नए नियम के लागू होने के बाद, डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर्मचारियों और संचालन प्रणाली में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। सरकार का मानना है कि यह कदम ऑनलाइन गेमिंग को जिम्मेदार और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

इस प्रकार, ऑनलाइन मनी गेमिंग में नियम तोड़ने वालों के लिए अब कोई ढील नहीं रहेगी। केंद्र सरकार का यह सख्त प्रस्ताव न केवल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा बल्कि गेमिंग कंपनियों और उनके स्टाफ को भी जिम्मेदार ठहराएगा। डिजिटल गेमिंग के क्षेत्र में पारदर्शिता और अनुशासन बढ़ाने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.